



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 384]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 30, 2019/कार्तिक 8, 1941

No. 384]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 30, 2019/KARTIKA 8, 1941

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 18 अक्टूबर 2019

सं. टीएएमपी/90/2016-पीपीटी.— महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद् द्वारा परादीप पत्तन न्यास (पीपीटी) के मौजूदा दरमानों की वैधता का विस्तार, संलग्न आदेशानुसार करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामल संख्या टीएएमपी/90/2016-पीपीटी

परादीप पत्तन न्यास

—

आवेदक

गणपूर्ति

- (i) श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
- (ii) श्री रतन सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(अक्टूबर, 2019 के 10वें दिन पारित)

मामला परादीप पत्तन न्यास (पीपीटी) के मौजूदा दरमानों की वैधता के विस्तार से संबंधित है।

2. पीपीटी के मौजूदा दरमानों का पिछला अनुमोदन इस प्राधिकरण द्वारा 15 सितंबर, 2017 के आदेश संख्या टीएएमपी/90/2016-पीपीटी द्वारा किया गया था जिसे भारत के राजपत्र में 1 नवंबर, 2017 के राजपत्र संख्या 422 में अधिसूचित किया गया था। आदेश में दरमानों की वैधता 31 मार्च 2019 निर्धारित की गई थी। तत्पश्चात, पीपीटी स्थित सभी महापत्तन न्यासों के मौजूदा दरमानों की वैधता 30 सितंबर, 2019 तक अथवा इस प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किये जाने वाले संशोधित दरमानों के कार्यान्वयन के प्रभावी होने की तारीख तक, जो भी पहले हो बढ़ा दी गई थी। वैधता का विस्तार करते समय पीपीटी को प्रशुल्क नीति 2018 के अनुरूप दरमानों के सामान्य संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

3.1. इसी पृष्ठभूमि में, पीपीटी ने अपने 27/30 जुलाई 2019 के पत्र संख्या एफए/आरई/123/2019/438 के द्वारा निम्नलिखित निवेदन किया:

- (i) पीपीटी के मौजूदा दरमानों की वैधता 30 सितंबर, 2019 को समाप्त हो रही है। इसलिए, पीपीटी के दरमानों के सामान्य संशोधन का प्रस्ताव तत्काल दायर करने की जरूरत है।
- (ii) पीपीटी में पीपीपी परियोजनाओं के अगले वर्ष आरंभ होने की संभावनाएं हैं। इसलिए, राजस्व बदल जायेगा क्योंकि कुछेक वर्तमान कार्गो पीपीपी टर्मिनलों को अंतरित हो जायेगा।
- (iii) उक्त स्थितियों में, वर्तमान राजस्व आकलन पीपीटी के दरमानों के संशोधन के मानक नहीं हो सकते।

3.2. इसके अतिरिक्त, उक्त पत्र के सिलसिले में, पीपीटी ने 20 अगस्त, 2019 के अपने पत्र संख्या एफए/आरई/123/2019 के द्वारा निम्नलिखित निवेदन किये:

- (i) पीपीटी में निम्नलिखित पीपीपी परियोजनाओं के अगले एक वर्ष के समय में आरंभ होने की संभावना है, और इस वर्ष आरंभ हुई पीपीपी परियोजनाओं को व्यौरा इस प्रकार है:-

क्र.सं.	पीपीपी प्रचालक का नाम	परियोजना का नाम	आरंभ होने की तारीख
1.	परादीप इंटरनैशनल कार्गो टर्मिनल प्रा.लि.	कंटेनरों सहित स्वच्छ कार्गो प्रहस्तन की बहुउद्देशीय बर्थ	04.04.2019
2.	जेएसडब्ल्यू परादीप टर्मिनल प्रा.लि.	लौह अयस्क आयातों के प्रहस्तन के लिए नई लौह अयस्क बर्थ	31.03.2020
3.	परादीप ईस्ट क्वे कोल टर्मिनल प्रा.लि.	ईक्यू-1,2 और 3 का मशीनीकरण	14.12.2020
4.	कलिंग इंटरनैशनल कोक टर्मिनल परादीप प्रा.लि.	कोयला आयातों के प्रहस्तन के लिए नई कोयला बर्थ	19.04.2021

- (ii) क्रमांक 2 पर दी गई परियोजना 31.08.2019 तक अंतरिम रूप से पूरी होनी थी और पूरी तरह से 31.03.2020 तक पूरी हो जायेगी। क्रमांक 4 पर दी गई परियोजना के अक्टूबर 2020 तक चालू होने की संभावना है यद्यपि चालू होने की नियम तारीख 19.04.2021 है।
- (iii) पीपीटी के राजस्व में पहले के पत्र में यथाउल्लिखित इन परियोजनाओं के आरंभ होने पर निश्चय ही प्रभाव पड़ेगा।

3.3. उपरोक्त के आधार पर पीपीटी ने अपने मौजूदा दरमानों की वैधता का विस्तार और 1 अक्टूबर, 2019 से एक वर्ष के लिए करने का अनुरोध किया है।

4.1. पीपीपी परियोजनाओं के आरंभ होने से पीपीटी के राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करने के उद्देश्य से, पीपीटी के कार्गो प्रोफाइल, जैसा वर्ष 2018-19 के दौरान सभी महापत्तन न्यासों द्वारा प्रहस्तित वस्तु वार यातायात के बारे में भारतीय पत्तन संघ (आईपीए) द्वारा दी गई सूचना से एकत्र किया गया है, और पीपीपी परियोजनाओं का कार्गो प्रोफाइल जैसा संबंधित प्रशुल्क आदेशों से जुटाया गया है, निम्नवत् है:-

क्र.सं.	पीपीपी परियोजना	पीपीपी परियोजना का प्रोफाइल	निम्नलिखित वस्तुओं सहित पीपीटी का कार्गो प्रोफाइल
1	परादीप इंटरनैशनल कार्गो टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (7 फरवरी, 2013 को अधिसूचित प्रशुल्क आदेश संख्या टीएएमपी/35/2008-केपीटी के साथ पठित 13.02.2014 का प्रशुल्क आदेश संख्या टीएएमपी/10/2014-पीपीटी)	(i) लौह और इस्पात उत्पाद अलूमीनियम इनगोट्स, पिग आयरन, तैयार उर्वरक खाद्यान्न और चीनी। (ii) कंटेनर्स	(i) लौह और इस्पात उत्पाद (ii) तैयार उर्वरक (iii) ब्रेक बल्क (iv) कंटेनर्स

2.	जेएसडब्ल्यू परादीप टर्मिनल प्रा.लि. (5 जून 2014 का प्रशुल्क आदेश संख्या टीएएमपी/28/2014-पीपीटी)	हर प्रकार का लौह अयस्क	लौह अयस्क और लौह अयस्क पैलेट्स
3.	परादीप ईस्ट क्वे कोल टर्मिनल प्रा.लि. (21 फरवरी 2014 का प्रशुल्क आदेश संख्या टीएएमपी/12/2014-पीपीटी)	ताल कोयला	ताप कोयला
4.	कलिंग इंटरनैशनल कोक टर्मिनल परादीप प्राइवेट लिमिटेड (2 जनवरी 2017 का टीएएमपी/68/2016-पीपीटी)	कोयला (हर प्रकार का)	(i) ताप कोयला (ii) कोकिंग कोयला (iii) अन्य कोयला

4.2. उक्त सारणी से यह प्रतीत होता है कि पीपीटी द्वारा संचालित बर्थों से कार्गो का पीपीटी ग्राहियों द्वारा प्रचालित की जाने वाली बर्थों पर अंतरण को वर्जित नहीं किया जा सकता, जैसा कि पीपीटी ने 30 जुलाई, 2019 के अपने पत्र में निवेदन किया है।

4.3. पीपीटी के दरमानों का निर्धारित 2019-20 से आरंभ करने 2021-22 तक की 3 वर्ष की अवधि के प्रशुल्क चक्र के लिए करना होगा और ऐसा संविधि के अनुसार वर्ष 2019-20 में किसी उपयुक्त प्रभावी तारीख से होगा। पीपीटी द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, जैसी ऊपर पैरा 3.2 में चर्चा की गई है, स्वच्छ कार्गो और कंटेनर्स प्रहस्तन की एक परियोजना 4 अप्रैल, 2019 से पहले ही चालू हो गई है। लौह अयस्क प्रहस्तन करने वाली एक और परियोजना अंतरिम रूप से 31 अगस्त, 2019 तक पूरी होने की प्रत्याशा है। इसका अर्थ यह हुआ कि वर्ष 2019-20 में दो परियोजनाओं का प्रचालन ही पीपीटी पर प्रभाव डालेगा। ऐसी स्थिति में, यह प्राधिकरण पीपीटी द्वारा उजागर किये गए बिंदुओं को स्वीकार करने को प्रवृत्त है कि महापत्तन न्यास प्रशुल्क नीति 2018 के खंड 2.5 के अनुसार 2018-19 (वाई 3) के यातायात के आधार पर राजस्व आकलन करना 2021-22 तक के प्रशुल्क चक्र के लिए लागू पीपीटी के दरमानों के संशोधन का मानक नहीं हो सकता।

5. चूंकि पीपीटी के मौजूदा दरमानों की विस्तारित वैधता 30 सितंबर, 2019 को समाप्त गयी है, और पीपीटी द्वारा दायर (किये जाने वाले) प्रस्ताव में लगने वाले अपेक्षित समय को ध्यान में रखते और कि पीपीटी के दरमानों में निर्वात से बचने के लिए यह उपयुक्त समझ जाता है कि पीपीटी के मौजूदा दरमानों की वैधता का विस्तार 30 सितंबर, 2019 से आगे किया जाए।

6. परिणाम में, और ऊपर दिये गए कारणों के लिए तथा सामूहिक विचार-विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण पीपीटी के मौजूदा दरमानों का वैधता का विस्तार एक वर्ष के लिए अर्थात् 1 अक्टूबर, 2019 से 30 सितंबर 2020 तक करने करता है। पीपीटी को प्रशुल्क नीति 2018 के आधार पर 30 जून 2020 तक अपना प्रस्ताव दायर करने की सलाह भी दी जाती है।

7. इस संबंध में, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पीपीटी के दरमानों को वैधता के विस्तार को, जो पीपीटी की अनन्य स्थिति के आधार पर किया गया है, किसी अन्य महापत्तन न्यास/ बीओटी प्रचालक द्वारा अपनी प्रशुल्क वैधता में विस्तार के लिए पूर्वोदाहरण के रूप में उद्धरित न किया जाए।

टी. एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./267/19]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 18th October, 2019

No. TAMP/90/2016-PPT.—In exercise of the powers conferred by Sections 48 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates of the Paradip Port Trust (PPT) as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major PortsCase No. TAMP/90/2016-PPT**Paradip Port Trust**

Applicant**QUORUM**

- (i) Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii) Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER(Passed on this 10th day of October, 2019)

This case relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates (SOR) of the Paradip Port Trust (PPT).

2. The existing SOR of PPT was last approved by this Authority vide Order No. TAMP/90/2016-PPT dated 15 September 2017 which was notified in the Gazette of India on 1 November 2017 vide Gazette No. 422. The Order prescribed the validity of the SOR till 31 March 2019. Thereafter, the validity of the existing SOR of all the Major Port Trusts including PPT was extended till 30 September 2019 or till the effective date of implementation of the revised SOR to be notified by this Authority, whichever is earlier. While extending the validity, the PPT was requested to file its proposal for general revision of Scale of Rates following Tariff Policy, 2018.

3.1. In this backdrop, the PPT vide its letter No. FA/RE/123/2019/438 dated 27/30 July 2019 has submitted as follows:

- (i) The validity of present SOR of PPT is expiring on 30 September 2019. Therefore, the revision proposal of general SOR of PPT needs to be filed immediately.
- (ii) The PPP projects in PPT are likely to be commissioned in next year. Therefore, the revenue generation will change because some of the existing cargo may get diverted to this PPP terminals.
- (iii) Under the above circumstances, the present revenue estimation may not be yardstick for revision of SOR of PPT.

3.2. Further, in continuation to the above letter, the PPT vide letter No. FA/RE/123/2019 dated 20 August 2019 has submitted as follows:

- (i) The following PPP projects in PPT are likely to be commissioned in next one year's time and the PPP projects commissioned during current financial year are furnished below:

Sr. No.	Name of the PPP Operator	Name of the Projects	Date of Commissioning
1.	Paradip International Cargo Terminal Pvt. Ltd.	Multi Purpose berth to handle clean cargo including containers.	04.04.2019
2.	JSW Paradip Terminal Pvt. Ltd.	New Iron Ore Berth for handling of Iron Ore exports.	31.03.2020
3.	Paradip East Quay Coal Terminal Pvt. Ltd.	Mechanization of EQ-1,2 & 3 berths.	14.12.2020
4.	Kalinga International Coal Terminal Paradip Pvt. Ltd.	New Coal Berth for handling of coal imports	19.04.2021

- (ii) The project at Sr. no. 2 will be completed provisionally by 31.08.2019 and overall completion will be by 31.03.2020. The project indicated at Sr. no. 4 is very likely to be commissioned by October 2020 even though the scheduled commissioning date is 19.04.2021.
- (iii) The impact on the revenue generation of PPT, as indicated in earlier letter, will definitely undergo a change after commissioning of these projects.

3.3. Based on the above, the PPT has requested to extend the validity of the present SOR for a further period of one year w.e.f. 1 October 2019.

4.1. In order to analyse the impact of commissioning of the PPP Projects on the revenue generation of PPT, the cargo profile of PPT as gathered from the information furnished by the Indian Ports Association (IPA) about the commodity wise traffic handled by all Major Ports during the year 2018-19 and the cargo profile of the PPP Projects as gathered from the respective Tariff Orders are given below:

Sl. No.	PPP Project	Cargo Profile of the PPP Project	Cargo Profile of PPT includes the following commodities.
1	Pradaip International Cargo Terminal Private Limited. (Tariff Order No. TAMP/10/2014-PPT dated 19 February 2014 read with tariff Order No. TAMP/35/2008-KPT notified on 07 February 2013)	(i) Iron and Steel Products, Aluminum Ingots, Pig Iron, Finished Fertilizers, Food grains and Sugar. (ii) Containers	(i) Iron and steel products. (ii) Finished Fertilizers (iii) Break Bulk (iv) Containers
2.	JSW Paradip Terminal Private limited (Tariff Order No. TAMP/28/2014-PPT, dated 5 June 2014)	All types of Iron ore	Iron ore and Iron ore pellets
3.	Paradip East Quay Coal Terminal Private Limited (Tariff Order No. TAMP/12/2014-PPT, dated 21 February 2014)	Thermal Coal	Thermal Coal
4.	Kalinga International Coal Terminal Paradip Private Limited (TAMP/68/2016-PPT, dated 02 January 2017)	Coal (All types)	(i) Thermal Coal (ii) Coking Coal (iii) Other Coal

4.2. It appears from the above table that shift of cargo from the berths operated by PPT to the berths that will be operated by the PPP Concessionaires cannot be ruled out, as submitted by PPT in its letter dated 30 July 2019.

4.3. The Scale of Rates for PPT has to be determined for the tariff cycle of 3 years period, commencing from 2019-20 to 2021-22, with a suitable effective date in the year 2019-20 as per the statute. As per the information furnished by PPT, as brought out at paragraph No. 3.2. above, one project for handling clean cargo and containers has already commissioned its operations on 4 April 2019. Another project to handle Iron Ore exports is expected to be provisionally completed by 31 August 2019. This implies that operation of two projects in the year 2019-20 would have impact on the PPT. That being so, this Authority is inclined to accept the point highlighted by the PPT that revenue estimation based on the traffic of 2018-19 (Y3), as per Clause 2.5. of the Tariff Policy for Major Port Trusts, 2018 is not the yardstick for revision of Scale of Rates of PPT applicable for the tariff cycle upto 2021-22.

5. Since the extended validity of the existing Scale of Rates of PPT has expired on 30 September 2019 and considering the time required for processing the proposal (to be) filed by the PPT and in order to avoid a vacuum in the Scale of Rates of PPT, it is felt appropriate to extend the validity of the existing Scale of Rates of PPT beyond 30 September 2019.

6. In the result, and for the reasons given above, and based on collective application of mind, this Authority extends the validity of the existing Scale of Rates of PPT for one year i.e. from 1 October 2019 to 30 September 2020. The PPT is also advised to file its proposal latest by 30 June 2020, following Tariff Policy, 2018.

7. In this connection, it is also made clear that the extension of the validity of the Scale of Rates for PPT, on account of the unique situation at PPT, shall not be quoted as a precedent by any Major Port Trust/ BOT Operator, for seeking extension of its tariff validity.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./267/19]